



न्यायालय श्रीमान् राजराजेन्द्रल मोहन रावलिमर के मध्य-मेपिल

पुनरोद्धारित घायिका क्रमांक :— R-1539-PB/2/14

प्राचीनतमिति दिनांकः—

मनराक्षण कर्ता / आवेदिका:— श्रीमति धिन्ताबाई पुत्री रामधन अग्रवाल

पर्ति८ बोतीला० जी अग्राह लुष्क निवासो श्राव सुखास

निवासी इतारा बाजार टिबरनो तहोटिपरनो जिला

2 ft off. per. 1917
- 31st October 1917
In nature high

३८७

କିମ୍ବା

उत्तरवादीगण।

:- १४ रामकृष्ण आ० रामदैन अग्राल मुते०

अन्तर्राष्ट्रीय अनादेकगण :--

अरिये वारसन :—

४३ श्रीमति मुद्रारबाई पाटेन दा मक्कुषण अंगताल

१२५ अनिल आरो रवि रामकृष्ण अग्रणी

४३० मोहन आरो रामकृष्ण अग्रवाल

४४४ राज्या आरोग्यमेहुषणे अग्रवाल

हरदा जिला हरदा

2- अमृतपुराण अटो रामधीन अग्रवाल

जिवास्ती 48 क्रिपतिनगर स्थर फोर्ट रोड अंदौरे १००००

० ३- श्रोमति मल्लाहाड़ ८
गते खसिये वारसान

४३० शालिग्राम ४३० मकन्द्राम अश्विनी

અંગે આલો આ શાકલિંગરા માત્રાની

१८५ अप्रृष्टातो शालिग राम अग्रवाल

निराजी छब्रपति दिनाजपौ वार्ड हरदा १३०५०

... 2 ...

4- श्रीमति मनोरमा बाई पुत्री रामधन अग्रवाल
पत्नि औ मधुकाशीजी अग्रवाल सराफ निवासी सराफ
चौक भोपाल जिला भोपाल

5- श्रीमति मुन्नीबाई उर्फ़ स्नेहलताबाई पुत्री रामधन
अग्रवाल पर्सिन विसोद कुमार अग्रवाल निवासी
श्रीमति श्रीमति श्रीमति श्रीमति
सी/इ ४० खंडवा जिला खंडवा ४०४०१

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मे ३०० रु० स०.

.....

उपरोक्त पुनरीक्षण कराएँ/ आवेदिका नगायालप

श्रीमान तहसीलादर मटोद्धय डरवा छद्दारा रु० ३०० २७ अ/

२०/१२-१३ मे पारित ग्रामीण दिनांक ८-५-१४ से व्यथित क्षुब्धि होकर
निम्न तथ्यों एवं आधारों पर ग्रंथ पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुतको जा
रही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगो 1539-पीबीआर/14 [चिंतावाइ/रम्भृत्तं]

जिला – हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.6.2014	<p>आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 8.5.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 28.4.2014 को तहसीलदार द्वारा स्वत्व सम्बन्धी निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया था, परंतु दिनांक 8.5.2014 अनावेदकगण के आवेदन पत्र पर स्वत्व के निराकरण हेतु 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रावधान है। अतः तहसीलदार द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा स्वत्व के निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था, परंतु बाद में 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि यदि पूर्व में तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्यवाही कर दी गई है, तो बाद में विधि के प्रावधानों के अनुरूप की</p>	

गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

